बातचीत के बिन्दु -18

मजदूर- किसान संघर्ष रैली.

सीटू-किसानसभा- खेतमजदूर यूनियन।

5 सितेम्बर, 2018 संसद के समक्ष।

बी.एस.एन.एल बचाओ ! राष्ट्र बचाओ !

सन 1991 में नव उदारवादी नीतियों को लागू करने के बाद सरकार द्वारा " राष्ट्रीय टेलिकॉम नीति " 1995 में लागू की गयी . इस नीति से पहले टेलिकॉम सेक्टर में सिर्फ सरकार का ही दबदबा था और सारी सेवाएँ सरकार ही देती थी . लेकिन 1995 के बाद प्राइवेट कंपनियों को भी टेलिकॉम सेक्टर में काम करने की इजाजत दे दी गयी . सरकार ने दलील दी कि प्राइवेट कंपनियों की वजह से इस सेक्टर में विश्व स्तर की सेवाएँ सस्ते दामो पर मिल सकेंगी और साथ साथ ये कंपनियां सरकार के लिए माँग पर कनैक्शन देने मे भी फायदेमंद रहेंगी .

सरकार का बहाना जो भी रहा लेकिन सच यह है कि 1995 की यह नीति (एनटीपी 1995) असल में टेलिकॉम सेक्टर को प्राइवेट व् कॉर्पोरेट के हाथो में देने की शुरुआत थी . यह बाद में साबित भी हो गया .1995 में प्राइवेट कंपनियों को मोबाइल सर्विस शुरू करने का लाइसेंस दे दिया गया . हालाँकि टेलीकम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट , यानि

सरकारी कम्पनी को इसका लाइसेंस नहीं दिया गया . यही समय था जब अपने देश में मोबाइल युग प्रारंभ हुआ . 2002 में जाकर सरकारी कंपनी बी एस एन एल को मोबाइल सर्विस शुरू करने की इजाजत दी गयी . 7 साल की यह देरी शायद इसीलिए थी कि प्राइवेट कंपनियां अपना वजूद बना सकें।

जिस वक़्त 1995 में ये लाइसेंस प्राइवेट कंपनियों को दिए गए थे, उस समय कें टेलिकॉम मंत्री श्री सुखराम ने कहा था कि सरकार को लाइसेंस फीस से 125,000 रूपए का राजस्व प्राप्त होगा . लेकिन 1995 से 1999 के बीच किसी भी प्राइवेट कंपनी ने सरकार को यह कहते हुए कि यह बहुत ज्यादा है राजस्व नहीं दिया . जब सुखराम ने इन कंपनियों को लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी तो एन.डी.ऐ की अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने मंत्री ही बदल दिया . और करोड़ो रूपए का राजस्व जो कि लाइसेंस फीस के रूप में आना था उसे माफ़ कर दिया गया .

हालाँकि बाद में सरकार ने फिर से प्राइवेट कंपनियों को तयशुदा लाइसेंस फीस का कुछ प्रतिशत देने के लिए कहा . यह अपने आप में इन कंपनियों को बहुत बड़ी छूट थी . प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की जो नीति कांग्रेस सरकार ने चलाई थी , उसे बड़े ही शानदार तरीके से बी जे पी सरकार ने आगे बढ़ाया .

असल में नवउदारवादी नीतियों को अटल बिहारी की सरकार ने बड़े ही तेज और जोरदार तरीके से चलाया . अपनी सार्वजनिक उपक्रम की

कंपनी " विदेश संचार निगम लिमिटेड ' जो कि विदेशी संचार का काम करती थी , उसे टाटा को बहुत ही सस्ते दामो पर बेच दिया गया . आज अपने देश का पूरा संचार तंत्र और व्यापार प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों द्वारा संचालित होता है और सरकार की कोई भागीदारी इसमें नहीं है .

उस समय की बी जे पी सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को अपना ज्यादा से ज्यादा सहयोग दिया . उस समय लैंडलाइन और मोबाइल का लाइसेंस अलग-अलग देने का कानून था , " रिलायंस इन्फोकॉम " जो कि अम्बानी की कंपनी थी , उसके पास सिर्फ लैंडलाइन का लाइसेंस था. लेकिन बड़ी ही चालाकी से इस कंपनी ने देशभर में रोमिंग सेवा के साथ अपनी मोबाइल सेवा शुरू कर दी .हालाँकि इस वजह से इस कम्पनी का लाइसेंस रद्ध कर दिया जाना चाहिए था लेकिन उस समय के मंत्री श्री प्रमोद महाजन ने इस कंपनी को फायदा देने के लिए एक नयी नीति के तहत एक नये लाइसेंस की शुरुआत कर दी जिसे एकीकृत लाइसेंस का नाम दिया गया . इसकी वजह से लैंडलाइन और मोबाइल दोनों सेवाएँ इस एक लाइसेंस से दी जा सकती थीं .

हालाँकि प्राइवेट कंपनियों की इतनी सहायता की गयी लेकिन फिर भी बी.एस.एन.एल ने आपने आप को एक बड़ा खिलाड़ी साबित करते हुए दिसंबर 2004 के अंत तक अपने मोबाइल ग्राहकों की संख्या एयरटेल के ग्राहकों के बराबर कर ली. एक और खास बात यह हुई कि इतने कॉम्पीटीशन के बाबजूद भी 2004-05 में 10000 करोड़ का नेट मुनाफा कमाया .

प्राइवेट कंपनियों द्वरा बी.एस.एन.एल को बर्बाद करने की साजिश रची गयी .इनकी इस इच्छा को पूरी करने के वास्ते 2007 में कांग्रेस

सरकार ने इस कम्पनी के मोबाइल की 45 लाख लाइन बढाने के लिए उपकरणों के टेंडर को रद्द कर दिया .

बी जे पी की मोदी की नेतृतव बाली सरकार की बी एस एन एल को खतम करने की कोशिश जारी है . इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह टेलिकॉम सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों और कॉर्पोरेट का एकाधिकार हो जाए . अगर यह हुआ तो अपने देश के आम आदमी को इसका बुरा नतीजा भुगतना पडेगा . सबको विदित है कि सरकार द्वारा अम्बानी की कंपनी रिलायंस जिओ को किस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है . इस कम्पनी द्वरा ललचाने बाली दरो पर काम करने से टेलिकॉम उद्योग में उथल-पुथल मच गयी है. अपने पैसो के दम पर जिओ ने अपने दामो में इतनी कमी कर दी है कि भारत में काम करने वाली इस सेक्टर की सभी कंपनियां हिल सी गयी हैं . कुछ छोटी मोटी कंपनियां बंद हो चुकी है . और तो और विदेशी कोम्पनी वोडाफोन को भी एक भारतीय कंपनी आईडिया सेलुलर से हाथ मिलाना पड़ा है . असल में तो जिओ या फिर एक दो कंपनिया भारत में जब बच जायेंगी और उनका एकाधिकार हो जायेगा , तब उनका असली चेहरा सामने आयेगा और उनकी दरें कितनी ही गुना बढ़ा दी जायेंगी.

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खुले रूप से मुकेश अम्बानी की मदद की जा रही है ताकि टेलिकॉम सेक्टर में उनकी मोनोपोली हो जाए . और तो और एक विज्ञापन में भी मोदी जी को रिलाइंस जिओ के उपयोग के

लिए कहते हुए दिखाया गया है .समझने की जरुरत है कि प्रधानमंत्री जी ने प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा देने का विज्ञापन कर दिया जबकि देश में टेलिकॉम सेक्टर की पब्लिक सेक्टर कम्पनी मौजूद है . एक और बात , डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्यूनिकेशन के सचिव जिसने अम्बानी द्वारा जिओ की घातक दरो का विरोध किया था , उसे भी हटा दिया गया .

जैसा कि विदित है कि बी जे पी की सरकार बी एस एन एल को खतम करने की कौशिश कर रही है . सरकार ने बी एस एन एल के टुकड़े कर दिए .सितम्बर 2017 में सरकार ने बी एस एन एल की एक सहायक टावर कंपनी की शुरुआत की . बी एस एन एल के 70000 टावर इस कंपनी को दे दिए गए . सरकार का यह कहना था कि अलग सहायक कंपनी में टावर दिए जाने से प्रबंधन में आसानी रहेगी लेकिन असलियत में तो उद्देश्य बी एस एन एल को कमजोर करना था . धीरे धीरे यह सभी टावर बड़ी होशियारी से प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चले जायेंगे . असल में यह मोदी जी का एक अखड्पने कदम है जिसकी वजह से बी एस एन एल की हालत एक लंगडी बतख के समान हो जायेगी .सरकार का इन मोबाइल टावरों को लेने का कोई हक नहीं है . इन सभी मोबाइल टावर्स में को बनाने में सरकार का कोई हाथ या सहयता नहीं है . बी एस एन एल के कर्मचारियों ने अपना खून-पसीना एक कर इनको बनाया है . इन 70000 टावरों को लेने के बाद बी एस एन एल के राजस्व में भारी कमी आ जायेगी जिसकी वजह से यह बीमारू हालत में आ सकती है . मोदी जी की सरकार असल में यही चाहती है .

2006 से 2012 तक बी एस एन एल द्वारा नेटवर्क बढाने के उद्देश्य से उपकरण लेने के करीब करीब सभी टेंडर रदद कर दिए गए . इसका सीधा सीधा फायदा प्राइवेट कंपनियों को मिल गया . चूंकि बी एस एन एल 6 साल के लम्बे अंतराल में कोई भी उपकरण खरीद नहीं कर पायी , इसकी गुणवत्ता में गिरावट लाजमी थी जिसकी वजह से उपभोक्ताओं ने इससे मुंह मोड़ लिया . और इस तरह इस हालत का फायदा उठाते हुए प्राइवेट कंपनियों का बाज़ार पर कब्जा हो गया .

बी एस एन एल को इसका बहुत नुक्सान हुआ . लेकिन इसमें काम कर रहे कर्मचारियों ने भी हिम्मत न हार कर अपना संघर्ष जारी रखा . नए से नए आयाम शुरू किये गए . इसी की वजह से आज भी बी एस एन एल एक जीवंत कम्पनी के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है .कोई शक नहीं 2017 में इसके उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा हुआ जो कि प्राइवेट कंपनियां जैसे एयरटेल , वोडाफोन , आईडिया इत्यादि से ज्यादा रहा .

बी एस एन एल में काम कर रहे कर्मचारी लगातार संघर्षशील रहे ताकि इसको प्राइवेट होने से बचाया जा सके . हालाँकि पिछले 18 वर्षो में सभी सरकारों ने बहुत कोशिश की कि विनिवेश हो जाए लेकिन कर्मचारियों की समझदारी और संघर्ष ने सरकार की पहल को नाकाम कर दिया . आज भी बी एस एन एल 100% सरकारी कंपनी है . बी एस एन एल सभी यूनियनें एंड ऑफिसर्स " द आल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ़ बी एस एन एल " (ऐ यू ऐ बी) के बैनर तले साँझा और अथक संघर्ष बनाए हुए हैं .. न जाने कितनी बार साँझा यूनाइटेड एक्शन किये गए ताकि सहायक टावर कामनी का गठन न हो सके . ऐ

यू ऐ बी के सभी सदस्य बी एस एन एल को बचा कर मजबूत करने हेतु संकल्पबद्ध हैं .

वर्कर यूनियन और ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सांझा तौर पर बहुत से संघर्ष किये ताकि सरकार पर दबाव डाल उपकरणों को प्राप्त कर सके जिससे बी एस एन एल का बढाव हो पाए . इसीका नतीजा है कि 2013 के बाद इन उपकरणों को बी एस एन एल को उपलब्ध कराया गया . साँझा रूप से इन्होने कई आन्दोलन किये ताकि बी एस एन एल की गुणवत्ता बढ़ सके .2011 में बी एस एन एल ने उपभोक्ताओ के लिए भी स्कीम शुरू की जिसे उन्होंने " कस्टमर डिलाइट मूवमेंट का नाम दिया . अपना आधार बढाने के लिए इस स्कीम के तहत उन्होंने बहुत सी गतिविधियाँ की .2016 में यूनियन और एसोसिएशन ने मिलकर एक और मूवमेंट खड़ा किया जिसे उन्होंने नाम दिया सर्विस विद अ स्माइल. इनके साँझा प्रयास की वजह से बी एस एन एल के हालत अच्छे हुए और घाटे से उभर कर 2014-15 में फायदे की तरफ अग्रसर हुई

बी एस एन एल को ख़त्म करने की सरकारी नीति से सिर्फ कर्मचारियों और ऑफिसर का ही सरोकार नहीं है बल्कि यह आम आदमी की जिन्दगी से जुड़ा प्रश्न है .इसका सीधा असर आम आदमी पर है . आज के इस युग में टेलिकॉम सर्विस और डाटा उपयोग आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है . सरकार को कोई हक नहीं है कि आम आदमी को प्राइवेट कंपनी और कॉर्पोरेट तथा इनकी मोनोपोली की दया पर छोड़ दे . इसीलिए सभी सेक्टर के वर्कर्स को बी एस एन एल संघर्ष से जुड़ने की जरुरत है . ताकि बी एस एन एल की रक्षा की जा

सके जिसकी वजह से आम आदमी को इसकी सर्विस और डाटा सर्विस बहनीय दामो मिल सके .

5 सितम्बर की मजदूर किसान रैली बी एस एन एल और सार्बजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए है . यह इस मांग के लिए पुरजोर आवाज उठाने के लिए है जिससे नवउदारवादी नीतियों को उल्टा जाए ताकि सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट कंपनी के हाथो न बेचा जा सके और आम आदमी का धन प्राइवेट कॉर्पोरेट के हाथो में न जा सके फिर वो देसी हो या विदेशी .

एकजुटता बनाओ ! संघर्ष करों !

- 0.1 प्रतिशत के लिए काम करने वाली सरकारों के बिरुद्ध।
- 99.9 प्रतिशत के लाभ की नीतियों के लिए ।

---सरकार की नीति विरुद्ध ..
---वर्कर्स फ्रेंडली नीतियों के पक्ष में ..